Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

21-22 सितम्बर 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. भारत और FAO तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से ब्लू पोर्ट अवसंरचना विकसित करने के लिए साझेदारी करेंगे।

19 सितंबर, 2025 को, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग (DoF) ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के सहयोग से तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) के अंतर्गत ब्लू पोर्ट विकास पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य भारत के मत्स्य बंदरगाहों को स्मार्ट, टिकाऊ और तकनीक-संचालित ब्लू पोर्ट में बदलना है।

- **भारत सरकार ने वनकबारा (दीव), जखाऊ (गुजरात) और कराईकल (पुदुचेरी) में तीन स्मार्ट और एकीकृत मछली पकड़ने के बंदरगाहों के विकास के लिए पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें कुल 369.8 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया गया है, जो बड़े पैमाने पर ब्लू पोर्ट बुनियादी ढांचे की दिशा में पहला कदम है।**

- **TCP ढांचे के तहत, FAO योजना, डिज़ाइन, प्रबंधन और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा। यह साझेदारी भारत के बंदरगाह आधुनिकीकरण को सतत मत्स्य पालन में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और पर्यावरण प्रबंधन के वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएगी।**

Key Points:-

(i) ब्लू पोर्ट्स को 5वीं पीढ़ी (5G) कनेक्टिविटी, AI, स्वचालन प्रणाली, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उपग्रह-आधारित नेविगेशन और सेंसर-संचालित निगरानी जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा, जिससे बंदरगाह संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

(ii) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) के साथ संरेखित, ये बंदरगाह पर्यावरण अनुकूल आधुनिकीकरण को अपनाएंगे, जिससे टिकाऊ प्रथाओं, बेहतर संसाधन प्रबंधन और भारत की मत्स्य निर्यात क्षमता को बढ़ावा सुनिश्चित होगा।

(iii) ब्लू पोर्ट मॉडल में नवीकरणीय ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट प्रबंधन, उन्नत कोल्ड चेन और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए लॉजिस्टिक्स के साथ-साथ मछुआरों, सहकारी समितियों और बंदरगाह संचालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होंगे।

2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन (CCC) का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर, 2025 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय सेना की पूर्वी कमान

के मुख्यालय विजय दुर्ग (पूर्व में फोर्ट विलियम) में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन (CCC) का उद्घाटन किया।

• 15 से 17 सितंबर, 2025 तक आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन, "सुधारों का वर्ष: भविष्य के लिए परिवर्तन" विषय के तहत आयोजित किया गया था और इसमें भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और भविष्य की तत्परता पर जोर दिया गया था।

• 16वीं CCC ने सेना के आधुनिकीकरण, सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच संयुक्तता बढ़ाने और भविष्य के बहु-डोमेन युद्ध परिदृश्यों के लिए परिचालन तत्परता को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'भारतीय सशस्त्र बल विजन 2047' जारी किया, जो 2047 में भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी के साथ भारतीय सशस्त्र बलों को एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित और एकीकृत बल में बदलने के लिए एक व्यापक रोडमैप है।

Key Points:-

(i) सेवा प्रमुखों ने भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना की शिक्षा शाखाओं के विलय की घोषणा की, जिससे एक एकीकृत त्रि-सेवा शिक्षा कोर का गठन किया जा सके, जिसका उद्देश्य तीनों सेवाओं में प्रशिक्षण और शैक्षणिक मानकों को सुव्यवस्थित करना है।

(ii) परिवर्तन एजेंडे के एक भाग के रूप में, सशस्त्र बलों ने भारत में तीन नए संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। ये स्टेशन विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर समन्वय, संसाधन अनुकूलन और संयुक्त परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ावा देंगे।

(iii) सम्मेलन में सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों, सशस्त्र बलों के वरिष्ठ कमांडरों और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।

3. भारत सरकार ने पूरे भारत में स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2025 अभियान का 9वां संस्करण लॉन्च किया।

17 सितंबर, 2025 को, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत 15-दिवसीय राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान, स्वच्छता ही सेवा (SHS 2025) के 9वें संस्करण का शुभारंभ किया। "स्वच्छोत्सव" थीम वाला यह अभियान 2 अक्टूबर, 2025 को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में समाप्त होगा।

• यह अभियान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था।

• पूर्वावलोकन कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सी.आर. पाटिल तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

• केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने गुजरात के सूरत और नवसारी जिलों के लिए सफाईमित्र सुरक्षा कोष हेतु 8-10 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, जिससे एसएचएस 2025 अभियान के तहत सफाई कर्मचारियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित किए जा सकें।

Key Points:-

(i) SHS 2025 का आयोजन "स्वच्छता उत्सव" थीम के अंतर्गत किया जा रहा है और इसका उद्देश्य पूरे भारत में सार्वजनिक स्वच्छता अभियानों में लाखों नागरिकों को शामिल करना है। यह अभियान स्थायी स्वच्छता परिणाम प्राप्त करने में जन भागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी पर ज़ोर देता है।

(ii) यह पहल पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: उपेक्षित स्थानों को समाप्त करने के लिए स्वच्छता लक्ष्य इकाइयां (CTUs); शहरव्यापी स्वच्छता के लिए स्वच्छ सार्वजनिक स्थान (CPS); श्रमिक कल्याण के लिए सफाई मित्र सुरक्षा (SMS) शिविर; पर्यावरण अनुकूल समारोहों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ हरित उत्सव (CGF); और ODF+ गांवों और स्वच्छ सुजल गांव मॉडल की घोषणा के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से वकालत।

(iii) 25 सितंबर, 2025 को "एक दिन, एक घंटा, एक साथ" शीर्षक से एक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक श्रमदान आयोजित किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक सामूहिक रूप से अपने आस-पास की सफाई के लिए एक घंटा समर्पित करेंगे, जिससे समुदाय-नेतृत्व वाली स्वच्छता के अभियान के दृष्टिकोण को बल मिलेगा।

4. ओडिशा की कोराटिया टेक्नोलॉजीज ने स्वदेशी UWROVs के लिए भारतीय नौसेना के साथ 66 करोड़ रुपये का अनुबंध हासिल किया।

सितंबर 2025 में, ओडिशा स्थित डीप-टेक स्टार्टअप कोराटिया टेक्नोलॉजीज ने भारतीय नौसेना (IN) के साथ स्वदेशी रूप से निर्मित अंडरवाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (UWROVs) की आपूर्ति के लिए 66 करोड़ रुपये (लगभग 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का अनुबंध किया। यह सौदा नौसेना में भारत निर्मित UWROVs की पहली बड़े पैमाने पर तैनाती का प्रतीक है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करता है।

- **इस समझौते के तहत, कोराटिया टेक्नोलॉजीज जलसिम्हा, जलदूत और नव्या की आपूर्ति और रखरखाव करेगी, जो एआई-सक्षम पानी के नीचे और सतह पर चलने वाले वाहन हैं, जिन्हें विविध नौसैनिक संचालन, निरीक्षण और निगरानी कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है।**

- **इन UWROVs का लागत-कुशल और किफायती डिजाइन विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करता है, जिससे भारत को व्यापार प्रतिबंधों और टैरिफ अनिश्चितताओं से बचने में मदद मिलती है, जबकि घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है।**

Key Points:-

(i) UWROVs को बांध और पुल निरीक्षण, समुद्र तल मानचित्रण, समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों की निगरानी और अन्य रणनीतिक और औद्योगिक कार्यों

के अलावा अपतटीय ऊर्जा परिसंपत्तियों के निरीक्षण के लिए तैनात किया जाएगा।

(ii) यह अनुबंध मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के भारत के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है, जो पानी के नीचे रोबोटिक्स और एआई-सक्षम नौसेना प्रौद्योगिकी में घरेलू क्षमताओं को बढ़ाता है।

(iii) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षमताओं से लैस, ये UWROVs चुनौतीपूर्ण पानी के नीचे के वातावरण में कुशलतापूर्वक काम कर सकते हैं, वास्तविक समय डेटा संग्रह, उन्नत नेविगेशन और नौसेना और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए बेहतर परिचालन सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

5. INSPIRE पुरस्कार 2025: मुजफ्फरपुर 7,403 छात्र विचारों के साथ राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में शीर्ष पर।

सितंबर 2025 में, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला INSPIRE अवार्ड-MANAK (मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज) 2025 के तहत राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा। जिले में निजी और सार्वजनिक दोनों स्कूलों से 7,403 नवीन छात्र विचार प्रस्तुत किए गए, जो सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है।

• 2025 में शीर्ष तीन प्रदर्शन करने वाले राज्य मुजफ्फरपुर, बिहार (7,403 विचार), बेंगलुरु शहरी, कर्नाटक (7,306 विचार) और बागलकोट, कर्नाटक (6,826 विचार) थे। ये रैंकिंग जिलों की सक्रिय भागीदारी और छात्र-नेतृत्व वाले नवाचारों के प्रोत्साहन को दर्शाती हैं।

• यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoST) और राष्ट्रीय नवाचार प्रतिष्ठान (NIF) द्वारा प्रदान किया जाता है। डीएसटी, स्कूली छात्रों के विज्ञान-आधारित नवाचारों की पहचान और पोषण हेतु स्वायत्त निकाय, NIF के साथ सहयोग करता है।

• कक्षा 6 से 10 तक के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। चयनित छात्रों को अपने मॉडल और प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिन्हें पहले ज़िला स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है।

Key Points:-

(i) नवीनतम 2025 रैंकिंग के लिए, जयपुर, राजस्थान (6,311 विचार); वैशाली, बिहार; और लखनऊ, उत्तर प्रदेश (6,182 विचार) ने शीर्ष 5 में समान रैंक साझा की, जो कई राज्यों में व्यापक छात्र नवाचार को उजागर करता है।

(ii) इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में स्कूली बच्चों से 10 लाख मूल विज्ञान और समाज-आधारित विचारों को प्राप्त करना है, जिससे जमीनी स्तर पर छात्रों के बीच रचनात्मकता, अनुसंधान रुचि और नवाचार को बढ़ावा मिले।

(iii) चयनित विचारों को जिला से राज्य स्तरीय मूल्यांकन के लिए आगे बढ़ाया जाता है, और शीर्ष 60 नवाचारों को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में INSPIRE (NLEPC) की राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

INTERNATIONAL

1. भारत को 2025-28 के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के CA और POC के रूप में पुनः चुना गया।

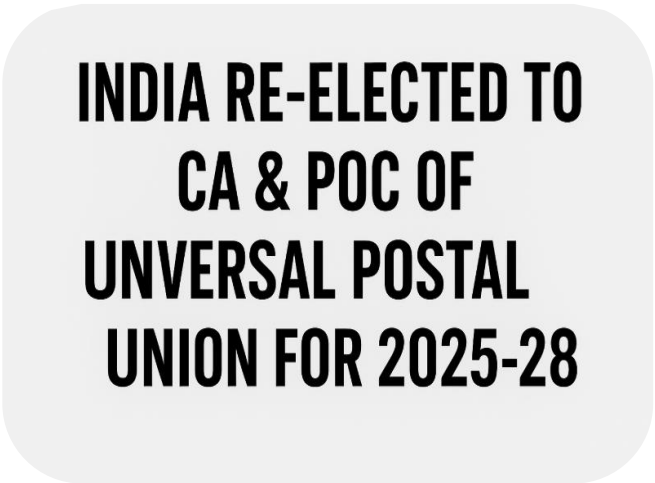

सितंबर 2025 में, दुबई में आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में, भारत को 2025-28 की अवधि के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के दो महत्वपूर्ण शासी निकायों में पुनः निर्वाचित किया गया, जिससे वैश्विक डाक प्रशासन में इसकी भूमिका सुदृढ़ हुई।

- **भारत ने 2025-2028 की अवधि के लिए एशिया-प्रशांत समूह के अंतर्गत UPU की प्रशासन परिषद (CA) और डाक परिचालन परिषद (PoC) के लिए पुनः चुनाव सुरक्षित कर लिया है।**
- **ये चुनाव दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 28वीं UPU कांग्रेस के दौरान हुए, जो 8 से 19 सितंबर, 2025 तक आयोजित की गई।**
- **यह पुनर्निर्वाचन UPU सदस्य देशों के भारत के डाक सुधारों, डिजिटल पहलों तथा नवाचार एवं वित्तीय समावेशन में उसके नेतृत्व के प्रति विश्वास को दर्शाता है।**

Key Points:-

(i) भारत 1876 से UPU का सदस्य है और लगभग 1.45 अरब लोगों को डाक नेटवर्क प्रदान करता है।

(ii) इसके साथ ही एक प्रमुख पहल की घोषणा की गई, वह थी UPI-UPU एकीकरण परियोजना, जो डाक विभाग, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और UPU के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसका उद्देश्य भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करना है, ताकि सुरक्षित, तेज, कम लागत वाले सीमा पार प्रेषण को सक्षम किया जा सके।

(iii) UPU एक संयुक्त राष्ट्र-विशिष्ट एजेंसी है जिसके 192 सदस्य देश हैं; CA के 41 सदस्य देश हैं और POC के 48 सदस्य देश हैं। इन निकायों में भारत की भूमिका का अर्थ है नीति विनियमन, परिचालन मानकों, डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय डाक सहयोग में प्रभाव।

2. विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने गंभीर जल तनाव पर प्रकाश डालते हुए 'वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट 2024' जारी की।

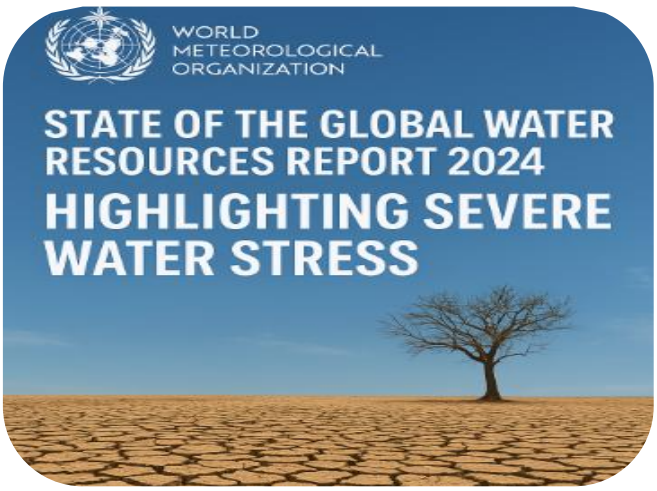

सितंबर 2025 में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने अपनी वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें वैश्विक जल असंतुलन की चेतावनी दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि केवल एक-तिहाई नदी घाटियों में ही सामान्य स्थिति दर्ज की गई, जबकि अधिकांश घाटियों में लगातार छठे वर्ष अत्यधिक जल प्रवाह का सामना करना पड़ा।

• वर्ष 2024 को 175 वर्षों के अवलोकन रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष बताया गया है, जिसमें वैश्विक सतह का तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.55 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है, जिससे वैश्विक जल तनाव और जलवायु से जुड़ी चुनौतियां बढ़ गई हैं।

• निष्कर्षों से पता चला है कि पिछले छह वर्षों से, 1991-2020 के औसत की तुलना में केवल 33.3% नदी जलग्रहण क्षेत्रों में सामान्य निर्वहन की स्थिति थी, जबकि लगभग 60% नदियों में अत्यधिक या कम प्रवाह का अनुभव हुआ, जो बिगड़ते जलविज्ञान असंतुलन को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) रिपोर्ट ने यह भी पुष्टि की कि 2024 सभी निगरानी क्षेत्रों में व्यापक ग्लेशियर हानि का लगातार तीसरा वर्ष होगा, जिसमें 450 गीगाटन बर्फ नष्ट हो जाएगी - जो 7 किमी x 7 किमी x 7 किमी बर्फ के ब्लॉक के बराबर है या 180 मिलियन ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल को भरने के लिए पर्याप्त है।

(ii) भविष्य की ओर देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र जल अनुमानों में चेतावनी दी गई है कि वर्तमान में 3.6 बिलियन लोगों को प्रति वर्ष कम से कम एक महीने अपर्याप्त जल की उपलब्धता का सामना करना पड़ता है, और यह आंकड़ा 2050 तक 5 बिलियन से अधिक हो जाने की उम्मीद है, जो वैश्विक जल प्रशासन और जलवायु अनुकूलन की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

3. महाराष्ट्र और फिनलैंड ने मुंबई के ऐतिहासिक ससून डॉक के आधुनिकीकरण के लिए सहयोग किया।

सितंबर 2025 में, महाराष्ट्र के बंदरगाह विकास मंत्री, नितेश नारायण राणे ने फ़िनलैंड के सहयोग से मुंबई के 150 साल पुराने ससून डॉक के लिए एक तकनीक-संचालित आधुनिकीकरण योजना की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य वर्तमान चुनौतियों का समाधान करते हुए इसकी ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करना है।

• अल्बर्ट अब्दुल्ला डेविड ससून द्वारा 1875 में निर्मित ससून डॉक, पश्चिमी भारत का पहला पूर्णतः निजी वेट डॉक था। शुरुआत में, यह कपास और अफीम का व्यापार करता था और बाद में मुंबई के मछुआरा समुदाय और मछली निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बन गया।

• लगभग 2,00,000 वर्ग फुट में फैला, ससून डॉक दक्षिण मुंबई के सबसे पुराने डॉक में से एक है। यह समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हज़ारों मछुआरों और मज़दूरों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

• गोदी को अत्यधिक क्षमता, अस्वास्थ्यकर मछली-संचालन प्रथाओं, आधुनिक सुरक्षा उपायों की कमी और परिचालन दक्षता में गिरावट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो इसकी स्थिरता और निर्यात क्षमता में बाधा डालती हैं।

Key Points:-

(i) प्रस्तावित उन्नयन में मॉड्यूलर अवसंरचना,

डिजिटल निगरानी प्रणाली, स्वचालित प्रकाश व्यवस्था, उन्नत मछली पकड़ने की तकनीक, पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं और सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक कुशल बंदरगाह के लिए एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन शामिल हैं।

(ii) इस परियोजना का शुभारंभ महावाणिज्य दूत एरिक एफ हॉलस्ट्रॉम और उप महावाणिज्य दूत ईवा निल्सन के नेतृत्व में फिनिश प्रतिनिधिमंडल के दौरे के साथ हुआ, जिन्होंने ससून डॉक में प्रमुख भारतीय हितधारकों के साथ बैठकें कीं।

(iii) इस पहल में लैमोर कॉर्पोरेशन (फिनलैंड), मिरासिस इंडिया, हेलिओस लाइटिंग सॉल्यूशंस (भारत) और रिवर रीसाइकल (फिनलैंड) सहित कई कंपनियां शामिल हैं, जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पर्यावरण अनुकूल नवाचारों और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

4. भारत और कनाडा व्यापार वार्ता पुनः शुरू करने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए।

भारत और कनाडा ने उच्च-स्तरीय वार्ता फिर से शुरू करने और विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है, जो द्विपक्षीय संबंधों में नए सिरे से बदलाव का संकेत है। यह कदम राजनयिक तनाव के बाद उठाया गया है और व्यापार, सुरक्षा और साझा मूल्यों को मज़बूत करने के लिए दोनों पक्षों की नई प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **भारत और कनाडा के अधिकारियों ने विदेश कार्यालय पूर्व परामर्श में बैठक करके व्यापार, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र पर केंद्रित द्विपक्षीय वार्ता तंत्र को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। इन परामर्शों का उद्देश्य ऊर्जा, असैन्य परमाणु, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, कानून प्रवर्तन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग को पुनः सक्रिय करना है।**

- **इससे पहले एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच कनानसकीस (जून 2025) में जी7 शिखर सम्मेलन में हुई बैठक थी।**

- **वे एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों को पुनः नियुक्त करने तथा अधिक व्यापक व्यापार समझौते (CEPA) की दिशा में एक कदम के रूप में प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते (EPTA) सहित रुकी हुई व्यापार वार्ताओं को पुनः आरंभ करने पर सहमत हुए।**

Key Points:-

(i) राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत और कनाडा के बीच व्यापार बढ़ता रहा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कनाडा को भारत का निर्यात लगभग 9.8% बढ़कर लगभग 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि कनाडा से आयात लगभग 2-2.3% घटकर लगभग 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।

(ii) यह नया सहयोग व्यापार से आगे भी जारी रहेगा। दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, और उच्च शिक्षा तथा कुशल पेशेवरों एवं छात्रों की गतिशीलता जैसे विकास क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएँ तलाश रहे हैं।

BANKING & FINANCE

1. EPFO ने त्वरित दावों, वास्तविक समय ट्रैकिंग और सरलीकृत PF पहुंच के लिए पासबुक लाइट लॉन्च किया।

18-19 सितंबर, 2025 को, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पासबुक लाइट नामक एक नई सुविधा शुरू की, साथ ही डाउनलोड करने योग्य अनुलग्नक के और प्रत्यायोजित अनुमोदन शक्तियों जैसे अन्य सुधार भी किए, जिसका उद्देश्य 70 मिलियन से अधिक ग्राहकों के लिए PF(भविष्य निधि) खाता प्रबंधन को तेज, अधिक पारदर्शी और अधिक सुविधाजनक बनाना है।

• सदस्य अब एक ही लॉगिन के ज़रिए EPFO सदस्य पोर्टल पर सीधे अपनी PF पासबुक (योगदान, निकासी और शेष राशि) का सरलीकृत, संक्षिप्त संस्करण देख सकते हैं। बुनियादी जानकारी के लिए अलग से पासबुक पोर्टल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है।

• स्थानांतरण प्रमाणपत्र (अनुलग्नक K), जो पहले केवल भविष्य निधि कार्यालयों के बीच आदान-प्रदान किया जाता था और सदस्यों को केवल अनुरोध पर दिया जाता था, अब सदस्य पोर्टल से PDF प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है। सदस्य भविष्य निधि स्थानांतरण आवेदनों की स्थिति पर भी नज़र रख सकते हैं और यह सत्यापित कर सकते हैं कि शेष राशि और सेवा अवधि सही ढंग से अपडेट की गई है।

Key Points:-

(i) PF हस्तांतरण, निपटान, धनवापसी, अग्रिम आदि के लिए अनुमोदन का अधिकार उच्च अधिकारियों (जैसे क्षेत्रीय PF आयुक्त) से हटाकर सहायक PF आयुक्तों और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को दे दिया गया है। इसका उद्देश्य दावों के निपटान में होने वाली देरी को काफी हद तक कम करना है।

(ii) ये सुधार आवेदनों (स्थानांतरण, दावों) की रीयल-टाइम ट्रैकिंग, PF सेवा अवधि और शेष राशि के स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड सुनिश्चित करते हैं, जो कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन लाभों की गणना के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही, अधिक पारदर्शिता से शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है।

(iii) मुख्य EPFO सदस्य पोर्टल में पासबुक लाइट को एकीकृत करके और सारांश जानकारी के लिए अलग-अलग पासबुक लॉगिन से बचकर, EPFO का लक्ष्य सर्वर लोड को कम करना और पहुँच को सुव्यवस्थित करना है। विस्तृत पासबुक पोर्टल उन लोगों के लिए सुलभ बना रहेगा जिन्हें पूर्ण विवरण (ग्राफ़, लेन-देन इतिहास) की आवश्यकता है।

2. PFRDA ने गैर-सरकारी ग्राहकों के लिए NPS के अंतर्गत मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) पेश किया, जो 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) शुरू करने की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी एक प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन को चिह्नित करता है।

• MSF गैर-सरकारी अंशधारकों को विभिन्न केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसियों (CRAs) में एक ही प्रान (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) के अंतर्गत कई योजनाएँ रखने की अनुमति देगा। इससे पहले, प्रत्येक अंशधारक प्रत्येक स्तर पर केवल एक ही निवेश विकल्प चुन सकता था और एक ही CRAs से जुड़ा होता था, जिससे लचीलापन सीमित हो जाता था।

Key Points:-

(i) यह ढाँचा पेंशन निधि (PFs) को विविध ग्राहक समूहों, जिनमें गिग और डिजिटल अर्थव्यवस्था के कर्मचारी, स्व-नियोजित पेशेवर और नियोक्ता सह-योगदान प्राप्त करने वाले कॉर्पोरेट कर्मचारी शामिल हैं, के लिए अनुकूलित योजनाएँ तैयार करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य NPS को अधिक समावेशी और विकसित होते कार्यबल ढांचे के अनुकूल बनाना है।

(ii) MSF के तहत, प्रत्येक योजना को कम से कम दो निवेश विकल्प प्रदान करने होंगे - मध्यम और उच्च जोखिम - जिसमें उच्च जोखिम वाले विकल्प में इक्विटी आवंटन 100% तक की अनुमति होगी, जबकि पहले इसकी अधिकतम सीमा 75% थी।

(iii) इससे ग्राहकों को उनकी निवेश इच्छा के अनुरूप व्यापक जोखिम-वापसी विकल्प उपलब्ध होते हैं।

3. DBS बैंक इंडिया जीएसटी संग्रह के लिए एजेंसी बैंक के रूप में आरबीआई द्वारा अधिकृत पहली विदेशी बैंक सहायक कंपनी बन गई है।

सितंबर 2025 में, डीबीएस बैंक इंडिया भारत में किसी विदेशी बैंक की पहली पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा वित्त मंत्रालय (MoF) के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की ओर से माल और सेवा कर (GST) भुगतान एकत्र करने के लिए एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया गया।

• DBS बैंक इंडिया का प्राधिकरण इसे GST संग्रह को सुविधाजनक बनाने, कर प्रशासन दक्षता को बढ़ाने और राष्ट्रीय पेंशन और कर ढांचे में एकीकृत सहज डिजिटल भुगतान समाधान के साथ व्यवसायों को प्रदान करने की अनुमति देता है।

Key Points:-

(i) बैंक अपने उद्यम डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, DBS आइडियल के माध्यम से जीएसटी संग्रह सेवाएं

प्रदान करेगा, जो वास्तविक समय लेनदेन अपडेट, तत्काल भुगतान पावती और डाउनलोड करने योग्य भुगतान सलाह का समर्थन करता है, जिससे कॉर्पोरेट्स के लिए अनुपालन और रिकॉर्डकीपिंग में सुधार होता है।

(ii) डिजिटल संग्रह के अलावा, करदाता DBS बैंक इंडिया शाखाओं में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT), रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और ओवर-द-काउंटर (OTC) भुगतान का भी उपयोग कर सकते हैं, जो विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भुगतान के कई लचीले तरीके प्रदान करते हैं।

(iii) DBS आइडियल व्यवसायों के लिए समर्पित ग्राहक सहायता भी सुनिश्चित करता है, जीएसटी अनुपालन प्रश्नों को कुशलतापूर्वक हल करने में सहायता करता है और उद्यम वित्तीय संचालन के साथ कर भुगतान प्रक्रियाओं के सुचारू एकीकरण को सुनिश्चित करता है।

4. IRDAI ने बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मार्केटप्लेस "बीमा सुगम" का अनावरण किया।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाने के लिए एक एकीकृत डिजिटल बाज़ार "बीमा सुगम" लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और पॉलिसीधारकों की सुविधा को बढ़ावा देना है।

- **बीमा सुगम ग्राहकों को एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा पॉलिसियों की तुलना, खरीद, नवीनीकरण, पोर्ट और दावे दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा।**

Key Points:-

(i) यह प्लेटफ़ॉर्म बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन (BSIF) द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड एक तकनीकी भागीदार है, जो सुरक्षित और स्केलेबल एकीकरण सुनिश्चित करता है।

(ii) शुरुआत में एक सूचना पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया, IRDAI की चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना के तहत दिसंबर 2025 तक संपूर्ण लेनदेन सेवाओं के साथ इसका पूर्ण पैमाने पर रोलआउट होने की उम्मीद है।

(iii) बीमा सुगम, IRDAI की "बीमा त्रिमूर्ति" (बीमा विस्तार और बीमा वाहक के साथ) का एक हिस्सा है और यह विकसित भारत 2047 के अंतर्गत "2047 तक सभी के लिए बीमा" के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. भारत गुवाहाटी, असम में दूसरे BIMSTEC युवा नेताओं के शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा।

सितंबर 2025 में, भारत ने 9 से 11 सितंबर तक गुवाहाटी, असम में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) युवा नेताओं के शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी की।

• शिखर सम्मेलन का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने किया, जिसमें BIMSTEC क्षेत्र के भावी नेताओं को एक साथ लाया गया।

• 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार (GoI) के सहयोग से किया गया था। इस संयुक्त प्रयास ने संरचित नेतृत्व और नवाचार-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से युवा-नेतृत्व वाले क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर किया।

Key Points:-

(i) इस कार्यक्रम में सात बिम्सटेक सदस्य देशों: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 से अधिक युवा नेताओं ने भाग लिया। विविध सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पृष्ठभूमि वाले युवा नेताओं की उपस्थिति ने क्षेत्रीय एकीकरण के एक सेतु के रूप में BIMSTEC की भूमिका को रेखांकित किया।

(ii) शिखर सम्मेलन भारत की विदेश नीति प्राथमिकताओं - पड़ोस प्रथम, एक्ट ईस्ट, तथा क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति (महासागर) के अनुरूप है।

(iii) उल्लेखनीय है कि BIMSTEC युवा नेताओं के शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण फरवरी 2025 में गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया था, जिसने क्षेत्रीय नीति निर्माण में युवाओं की निरंतर भागीदारी की नींव रखी।

IMPORTANT DAYS

1. संयुक्त राष्ट्र 18 सितंबर 2025 को छठा अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया।

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 18 सितंबर 2025 को 6वां अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया, जिसमें समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन प्राप्त करने और राष्ट्रों में लगातार लिंग वेतन अंतर को दूर करने की वैश्विक प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

• अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस की शुरुआत 2019 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 41वें सत्र के दौरान की गई थी।

• यह प्रस्ताव आइसलैंड, जो कि समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (EPIC) की संचालन समिति का सदस्य है, तथा इसके मुख्य सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड, पनामा, दक्षिण अफ्रीका और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।

Key Points:-

(i) 18 दिसंबर 2019 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने संकल्प A/RES/74/142 को अपनाया, जिसके तहत वेतन समानता पर वैश्विक वकालत को मजबूत करने के लिए हर साल 18 सितंबर को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में घोषित किया गया।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस का पहला आयोजन 18 सितंबर 2020 को हुआ, जिसने दुनिया भर में वेतन भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में प्रगति की निगरानी करने और संयुक्त कार्रवाई करने के लिए एक वैश्विक मंच की स्थापना की।

(iii) 2025 तक यह दिवस एक महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र पहल के रूप में विकसित हो चुका था, जो सतत विकास लक्ष्य (SDG) 8.5 के अनुरूप था, जो 2030 तक समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करता है, जो वेतन असमानताओं को दूर करने की तात्कालिकता को दर्शाता है।

2. विश्व बांस दिवस 2025-18 सितंबर को मनाया गया।

विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2025 को दुनिया भर में मनाया गया, जो इसका 17वाँ संस्करण होगा। यह दिवस बांस के पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ बांस आधारित उद्योगों में सतत उपयोग और निवेश को प्रोत्साहित करता है।

• विश्व बांस दिवस की स्थापना पहली बार 2009 में विश्व बांस संगठन (WBO) द्वारा बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 8वें विश्व बांस कांग्रेस (WBC) के दौरान की गई थी।

• पहला समारोह भी 18 सितम्बर 2009 को बैंकॉक में असम के कामेश सलाम के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जो 2007 से 2009 तक WBO के अध्यक्ष रहे।

• अपनी स्थापना के बाद से, विश्व बांस कांग्रेस ने वैश्विक बांस संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 12वीं विश्व बांस कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के तत्वावधान में ताइवान में आयोजित की गई थी, जबकि 13वीं विश्व बांस कांग्रेस 2026 में आयोजित होने वाली है, जो बांस विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जारी रखेगी।

Key Points:-

(i) भारत में, पूर्वोत्तर बांस सम्मेलन 2025 का आयोजन 9 सितंबर 2025 को गुवाहाटी, असम में किया गया। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक स्थायी बांस अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर चर्चा की गई और नवाचार एवं उद्यमिता के अवसरों पर प्रकाश डाला गया।

(ii) विश्व बांस दिवस 2025 का विषय "निवेश, CSR और जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना" था, जो बांस को टिकाऊ व्यापार मॉडल और सामुदायिक विकास पहलों में एकीकृत करने के वैश्विक प्रयासों के साथ संरेखित था।

3. IPC ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह का उद्घाटन किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के अंतर्गत कार्यरत भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) ने 17 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 5वें राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह (NPW) का उद्घाटन किया। यह आयोजन 23 सितंबर, 2025 तक जारी रहेगा।

• राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह (NPW) का 5वां संस्करण 17-23 सितंबर, 2025 तक मनाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों, नियामकों, शोधकर्ताओं और जनता के बीच प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं (ADRs) की रिपोर्टिंग के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है।

• 2025 NPW का आयोजन "आपकी सुरक्षा, बस एक क्लिक दूर: PvPI को रिपोर्ट करें" थीम के तहत किया जा रहा है। भारतीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम (NCC-PvPI) के लिए राष्ट्रीय समन्वय केंद्र के रूप में कार्यरत IPC, ADR रिपोर्टिंग के लिए सरलीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाश डालने की इस पहल का नेतृत्व कर रहा है।

Key Points:-

(i) इस कार्यक्रम में कई नई पहलों की शुरुआत की गई, जिनमें PvPI पर एक लघु फिल्म, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बहुभाषी फार्माकोविजिलेंस कॉमिक और त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड के माध्यम से आसान पहुंच के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया ऑनलाइन ADR रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म शामिल है।

(ii) फार्माकोविजिलेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। उल्लेखनीय है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) स्थित ADR निगरानी केंद्र को PvPI-रोगी सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला।

(iii) आंध्र प्रदेश के डेली कुमार टी को भारत में ADR रिपोर्टिंग को मजबूत करने और रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देने में उनके समर्पित योगदान के लिए PvPI-पेशेंट कनेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. खगोलविदों ने पृथ्वी के नए अर्ध-उपग्रह '2025 PN7' की खोज की, जो एक अर्जुन-श्रेणी का क्षुद्रग्रह है।

सितंबर 2025 में, खगोलविदों ने एक नए पृथ्वी-निकट क्षुद्रग्रह, '2025 PN7' की खोज की पुष्टि की, जिसे अर्जुन-श्रेणी के क्षुद्रग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जिसका नाम महाभारत के अर्जुन के नाम पर रखा गया है। यह पृथ्वी के अर्ध-उपग्रह के रूप में कार्य करता है, पृथ्वी के निकट रहते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है, और इसके लगभग 128 वर्षों तक इसी अवस्था में रहने की उम्मीद है।

• क्षुद्रग्रह 2025 PN7 का पहली बार अगस्त 2025 में अमेरिका के हवाई में हेलेकाला ज्वालामुखी पर स्थित पैनोरमिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पांस सिस्टम (PAN-STARRS) वेधशाला द्वारा पता लगाया गया था। इसके निष्कर्ष बाद में सितंबर 2025 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्च नोट्स में प्रकाशित हुए।

• इस खोज के साथ, पृथ्वी के ज्ञात अर्ध-उपग्रहों की कुल संख्या बढ़कर सात हो गई है, जिनमें 164207 कार्डिया (2004 जीयू9), 469219 कामो'ओलेवा (2016 एचओ3), 277810 (2006 एफवी35), 2013 एलएक्स28, 2014 ओएल339 और 2023 एफडब्ल्यू13 शामिल हैं।

Key Points:-

(i) यह क्षुद्रग्रह अपेक्षाकृत छोटा है, जिसका व्यास लगभग 19 मीटर (62 फीट) है, और इसकी धुंधली प्रकृति के कारण, इसे केवल शक्तिशाली दूरबीनों से ही देखा जा सकता है। इससे मानक अवलोकन उपकरणों से इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

(ii) पृथ्वी की तरह, 2025 PN7 भी एक वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी से लगभग 186,000 मील (299,337 किमी) की दूरी पर घूमता है, लेकिन इसकी औसत दूरी लगभग 238,855 मील (384,400 किमी) है, जो चंद्रमा की कक्षा की दूरी के बराबर है।

(iii) 2025 PN7 की खोज ग्रह विज्ञान में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ती है, जिससे खगोलविदों को पृथ्वी के सह-कक्षीय साथियों और पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रहों की दीर्घकालिक गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।

Static GK

Food and Agriculture Organisation (FAO)	महानिदेशक: Qu Dongyu	मुख्यालय: रोम, इटली
Indian Army (IA)	सेना प्रमुख (COAS) : जनरल उपेंद्र द्विवेदी	मुख्यालय: नई दिल्ली
Odisha	राजधानी:भुवनेश्वर	मुख्यमंत्री: मोहन चरण माझी
Assam	मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा	राज्यपाल: लक्ष्मण आचार्य
World Meteorological Organisation (WMO)	महासचिव: सेलेस्टे साउलो	मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)	अध्यक्ष: शिवसुब्रमण्यम रमन	मुख्यालय: नई दिल्ली
Maharashtra	मुख्यमंत्री: देवेंद्र फडणवीस	राजधानी: मुंबई
Canada	प्रधानमंत्री: मार्क कार्नी	गवर्नर-जनरल: मैरी साइमन